मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ''एआई इनोवेशन समिट 2025'' कार्यक्रम में पुस्तक ''प्राइवेसी इन एआई'' व दो दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया।

देश में सर्वाधिक सीए राजस्थान से हैं - भजन लाल

मुख्यमंत्री ने भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान के ''ए आई इनोवेशन समिट'' को संबोधित किया

- **मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि आमजन को सीए में बहुत विश्वास होता है। उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने व विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है।**

जयपुर, 22 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउटेंट देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा हैं तथा उनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउटेंट्स से आव्हान किया कि वे अपनी योग्यता, विचारों एवं मेहनत से राज्य के विकास में अधिक से अधिक भागीदार बनें तथा देश-प्रदेश की प्रगति में योगदान दें, जिससे विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को गति मिले।शर्मा शुक्रवार को भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान, जयपुर शाखा द्वारा आयोजित 'एआई इनोवेशन समिट 2025' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा सीए राजस्थान से हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीए नई तकनीक आने पर, कोई नया नियम बनने पर अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आने पर सबसे पहले उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं और समाज को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आमजन को सीए पर बहुत विश्वास होता है, उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने एवं इस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान भी डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया एआई मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारी सरकार नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी पर भी काम कर रही है।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास में नवीन तकनीकों एवं एआई का उपयोग कर राज्य को गुड गवर्नेंस की ओर ले जाया जा रहा है।

इससे पहले शर्मा ने 'प्राइवेसी इन एआई' पुस्तक तथा दो दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने आईसीएआई सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए 'एआई 2.0' कोर्स का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान, जयपुर शाखा के सदस्य सीए सतीश गुप्ता, सीए रोहित सहित बड़ी संख्या में सीए मौजूद रहे।

राहुल की मुंगेर यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी

- **राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने मुंगेर की ऐतिहासिक खानकाह मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख विद्वानों से मुलाकात की।**

मुंगेर, 22 अगस्त । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ''मतदाता अधिकार यात्रा'' आज छठे दिन बिहार के जमालपुर और मुंगेर पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य देशभर में मतदाता सूची में कथित धांधली और मतदाता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जन-जागरूकता फैलाना है।

राहुल गांधी के साथ यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल रहे। दोनों नेताओं ने मुंगेर स्थित ऐतिहासिक खानकाह मस्जिद का दौरा किया और वहां मुस्लिम समुदाय के प्रमुख विद्वानों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया और लोकतंत्र और वोटिंग अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर उनके रुख का समर्थन किया। यात्रा के अगले पड़ाव में राहुल गांधी बिहार के अन्य जिलों का दौरा करेंगे और मतदाता अधिकारों को लेकर जनसंवाद जारी रखेंगे।

ईडी ने जम्मू में कई जगहों पर रेड की

जम्मू, 22 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने शुक्रवार को जम्मू के विभिन्न स्थानों पर भूमि घोटाले के संबंध में पटवारियों, नायब तहसीलदारों और अन्य राजस्व अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने भूमि घोटाले और कस्टोडियन भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए पटवारी, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी की।

बूंदी जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 734 एमएम (करीब 29 इंच) बारिश होने से घरों में पानी घुस गया, मुख्य बाजार की सड़के जलमग्न हो गई तथा कई जगह बाढ़ के हालात बन गये।

बूंदी जिले में आठ घंटे में 29 इंच रिकॉर्ड बारिश

जिले की सभी नदियां उफान पर और अधिकांश बांध व तालाब लबालब

- **बूंदी जिले में 24 घंटे से बारिश हो रही है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच विभिन्न इलाकों में 29 इंच बारिश हुई, सबसे ज्यादा 338 मिलीमीटर बारिश नैनवां तहसील में हुई।**
- **तेज बहाव से गरडदा-बिजौलिया मार्ग पर पुलिया बहने से गरडदा, बिजौलिया, भोपतपुर तथा कई गांवों का भीलवाड़ा व बूंदी से सम्पर्क टूट गया है।**

बूंदी, 22 अगस्त (निसं)। बूंदी जिले में आठ घंटे में 29 इंच बारिश दर्ज की गई जिले में गत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिले के अधिकांश बांध लबालब हो गए और उनमें पानी की आवक जारी है।

मौसम विभाग के अनुसार बूंदी जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 734 मिलीमीटर (करीब 29 इंच) बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश नैनवां तहसील 338 एमएम, दूसरे स्थान पर केशोरायपाटन में 165 एमएम दर्ज की गई। वहीं सबसे कम बूंदी तहसील में 29 एमएम दर्ज हुई। इसी बीच जिले की सभी नदी-नाले लबालब हो गए हैं। घोड़ा पछाड़, मांगली, मेज, तालेड़ा, रीवा नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के चलते गरडदा-बिजौलियां मार्ग पर पुलिया बह गई और बहने से गरडदा, बिजौलियां, भोपतपुरा तथा आसपास के गांवों का भीलवाड़ा और बूंदी जिले से संपर्क टूट गया। खेत जलमग्न हो गए। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। नैनवा, कापरेन, केशोरायपाटन नमाना क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं घरों में पानी घुस गया है मुख्य बाजार सड़कें जलमग्न है। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया है, जिसने रेस्क्यू शुरू किया है तथा लोगों को जलभराव क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर निकाला जा रहा है। नैनवा में बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जर्जर भवन की छत गिर गई है। इस बीच, मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया और लोगों से नदी-नालों से दूर रहने को कहा।

गरडदा के उप सरपंच धन्नालाल गुर्जर ने बताया कि भीलवाड़ा क्षेत्र से रीवा नदी में अचानक उफान आया व पुलिया बह गई, सूचना के बावजूद प्रशासन का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना तो संसाधन उपलब्ध कराए और ना ही टीम भेजी।

उधर, जल संसाधन विभाग की कनिष्ठ अभियंता मंजू मीणा ने बताया कि जिले के अधिकांश बांध लबालब हो चुके हैं। केवल एक-दो बांध ही बचे हैं, जो अगले कुछ दिन पूरी तरह भर जाएंगे। जिले के दो से तीन बड़े बांध ओवरफ्लो हैं। बरधा बांध सहित कई बांधों में वापस चादर चलने लगी है। दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया। इलाके में खेत तालाब में बदल गए। फसलें चौपट हो गई। रीवा नदी में उफान के चलते बूंदी व भीलवाड़ा जिले के कई गांवों का संपर्क कट गया। बूंदी के कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण उत्पन्न हुए हालातों का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने शुक्रवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

इसी क्रम में, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवि वर्मा ने भी अतिवृष्टि से गंभीर रूप से प्रभावित अरनेठा व भीया गांवों का दौरा किया। जलभराव की स्थिति को देखते हुए सीईओ ट्रैक्टर में बैठकर गांवों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया।

संसद परिसर में घुसने की कोशिश करने वाला पकड़ा गया

- **पुलिस के अनुसार वह सुबह 5.50 बजे संसद परिसर की चारदीवारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था।**

नयी दिल्ली, 22 अगस्त। संसद भवन परिसर में एक शख्स ने शुक्रवार सुबह घुसने की कोशिश जिसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। नयी दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह लगभग 5:50 बजे संसद भवन की चारदीवारी पर एक व्यक्ति चढ़ ने की कोशिश कर रहा था। उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और दिल्ली पुलिस के जवानों ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि युवक ने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी राम (20 वर्ष) बतायी है।

एक अप्रेल से आयकर अधिनियम लागू होगा

- **राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दी।**

नयी दिल्ली, 22 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के मानसून सत्र में पारित आयकर अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार यह विधेयक अगले वर्ष पहली अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा। यह अधिनियम 1961 के आयकर के कानून का स्थान लेगा।

पंजाब नैशनल बैंक सीआरपीएफ कर्मियों को विशेष लाभ देगा

- **बैंक ने इस संबंध में सीआरपीएफ के साथ एम.ओ.यू. साइन किया**

नयी दिल्ली, 22 अगस्त । सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी ऋण प्रदाता पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ एमओयू किया है जिसके तहत बल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों को विशेष बीमा कवरेज और अन्य लाभ दिये जायेंगे। पीएनबी ने शुक्रवार को बताया कि अपनी प्रमुख योजना ''पीएनबी रक्षक प्लस'' के अंतर्गत वह सीआरपीएफ के सभी सेवारत कर्मियों और पेंशनभोगियों को उन्नत बीमा कवरेज और अन्य लाभ प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, रक्षक खाताधारक के आश्रितों और परिवारों को भी कई लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

राज्यसभा सत्र का राष्ट्रपति ने सत्रावसान किया

- **मानसून सत्र में राज्यसभा की कुल 21 बैठकें हुई।**

नयी दिल्ली, 22 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सचिवालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि गुरुवार को उच्च सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने के बाद राष्ट्रपति ने शुक्रवार को राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और 21 अगस्त को संपन्न हुआ। इस दौरान सदन की 21 बैठकें हुई।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रम सिंघे गिरफ्तार

उन्होंने सरकारी पैसे से सितम्बर 2023 में लन्दन की निजी यात्रा की थी

- **पूर्व राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की गिरफ्तारी के बाद शीर्ष अधिकारियों द्वारा सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल करने के मामलों की जांच तेज होने की संभावना है।**

कोलंबो, 22 अगस्त। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी पैसे से लंदन की निजी यात्रा करने के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि विक्रमसिंघे ने दस लोगों के साथ, साल 2023 के सितंबर महीने में लंदन की यात्रा की थी। यह यात्रा पूरी तरह से निजी थी पर इसका खर्च सरकारी कोष पर डाल दिया गया। श्रीलंका के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है।

इस महीने की शुरुआत में, पूर्व राष्ट्रपति के सचिव समन एकनायके और पूर्व निजी सचिव सैंड्रा परेरा से इस यात्रा की व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी।

विक्रमसिंघे 2022 से 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी गिरफ्तारी से शीर्ष अधिकारियों द्वारा सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल करने के मामलों की जाँच तेज़ होने की उम्मीद है। विक्रमसिंघे के बाद श्रीलंका की कमान अनुरा दिसानायके के हाथ में आ गई।

'आधार कार्ड को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाताओं की सूची हटाने के कारणों के साथ प्रकाशित की जाए।

रमेश ने कहा कि 14 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाता पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज अदालत ने आधार को एक वैध पहचान पत्र के रूप में फिर से मान्यता दी है, जिसे चुनाव आयोग को स्वीकार करना होगा।

कांग्रेस ने कहा ''आज सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं, जिसमें राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया है। अब तक चुनाव आयोग का रवैया अवरोधक रहा है और मतदाताओं के हितों के खिलाफ रहा है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमें एक प्रवर्तनीय अधिकार देता है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकता,।''

पीठ ने कहा, ''सभी राजनीतिक दल अगली सुनवाई की तारीख तक यह स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उन्होंने बाहर किए गए मतदाताओं द्वारा दावा पत्र दाखिल कराने में क्या भूमिका निभाई।'' अदालत ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंट बाहर किए गए मतदाताओं के दावे के फॉर्म जमा करें, उन्हें रसीद दी जाए।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत से अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को यह दिखाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए कि कोई मतदाता बाहर नहीं किया गया है।

'कमजोर सरकार भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह सब कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाता है कि दिल्ली में बैठे नेता कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के प्रभारी रंधावा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हैं क्योंकि वे पंजाब और राजस्थान में अपनी खुद की राजनीति में व्यस्त हैं। अशोक गहलोत और उनके खेमे के करीबी माने जाने वाले रंधावा पार्टी की बजाय गहलोत के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर जयपुर या राजस्थान के किसी भी हिस्से में भाजपा सरकार के खिलाफ एक भी गंभीर आंदोलन नहीं हुआ है तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं गंभीर गड़बड़ी है लेकिन कोई भी इसे सुधारने या पार्टी को पटरी पर लाने के लिए तैयार नहीं है।

पंचायत चुनावों पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, राज्य सरकार सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इलविए कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी। वहीं बाद में कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर उन्हें पद से हटाया गया था। अपील में कहा गया कि इन हटाए गए प्रशासकों की किसी प्रकार की विधिक हानि नहीं हुई है। नए चुनाव के बाद इन्हें वैसे भी हटाया जाना था। ऐसे में मामले में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द किया जाए।

'वैक्सीनेशन के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद सीजेआई ने दुर्लभ प्रशासनिक कदम उठाते हुए यह केस पारदीवाला की पीठ से हटाकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को सौंपा। 11 अगस्त 2025 को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति पारदीवाला और महादेवन ने दिल्ली नगर निगम और अन्य निकायों को आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने और उन्हें सड़कों पर दोबारा न छोड़ने का निर्देश दिया था। साथ ही, आठ हफ्तों में कम से कम 5,000 कुत्तों को रखने की क्षमता वाले शेल्टर बनाने का आदेश भी दिया गया था।

भारी बारिश से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लैस सेना की गांडीव डिवीजन की इन्फेंट्री रेजिमेंट के 80 जवानों की टीम ने दीगोद तहसील के निमोदा गांव में राहत एवं बचाव कार्य शुरु किए हैं। जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्यों में सुबह से जुटी हुई हैं। जिन क्षेत्रों में जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोटा शहर में भी जलभराव वाले क्षेत्रों से एसडीआरएफ एवं प्रशासन ने लोगों को नावों की सहायता से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

ट्रंप के वाणिज्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने का आरोप लगता है, तो यही आरोप यूरोप के कुछ हिस्सों पर भी लगाया जा सकता है।

नवारो के इस रुख का समर्थन करने वाले कहते हैं कि भारत की गतिविधियाँ केवल जरूरत से कुछ अधिक हैं इन लोगों के अनुसार, भारतीय कंपनियां रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर उसे ईंधन उत्पादों के रूप में निर्यात करके बड़ा मुनाफा कमा रही हैं -यह भले ही तकनीकी रूप से अनुमत हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से ''मुनाफाखोरी'' है। आलोचकों का जवाब है कि यह परिणाम उन्हीं प्रतिबंधों की संरचना का हिस्सा है, जिनका मकसद रूसी तेल को बाजार में बनाए रखते हुए उसकी कीमत सीमित करना था।

असल बहस यह नहीं है कि भारत नियम तोड़ रहा है, क्योंकि वह नहीं तोड़ रहा, बल्कि यह है कि क्या उसकी भूमिका उन प्रतिबंधों की भावना को कमजोर कर रही है, जो रूस की आय को घटाने के लिए लगाए गए थे।

यह बातचीत भी अब आगे बढ़ रही है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में नियमों को कड़ा किया है और 2026 तक रिफाइन्ड उत्पादों की उत्पत्ति के बारे में अधिक विस्तृत दस्तावेज़ीकरण की मांग शुरू की है। यह संकेत देता है कि पश्चिमी नीति निर्माता स्वयं उन ''कमियों'' को स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें नवारो उजागर कर रहे हैं, हालांकि उनकी भाषा अधिक आक्रामक है।

नवारो की आलोचना वॉशिंगटन की अपेक्षाओं और नई दिल्ली की प्राथमिकताओं के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। नवारो के समर्थकों के अनुसार, रूस के साथ भारत का ऊर्जा व्यापार, मॉस्को पर दबाव बनाने के सामूहिक प्रयासों के खिलाफ अवसरवाद दर्शाता है। जबकि, उनके आलोचक कहते हैं कि उनके दावे कानूनी हकीकतों, भारत की ऊर्जा निर्भरता, और खुद पश्चिम की रूसी ईंधन पर निर्भरता को नजरअंदाज करते हैं।

स्पष्ट है कि भारत का रूसी तेल आयात एक बड़े विवाद का केन्द्र बन गया है। विवाद इस बात पर है कि प्रतिबंध असल में कैसे काम करते हैं, वैश्विक ऊर्जा बाजार कैसे अनुकूलन करते हैं और भू-राजनीति किस तरह आर्थिक ज़रुरतों से टकाराती है। कोई इसे मुनाफाखोरी माने या व्यावहारिकता, यह अंततः डेटा पर नहीं बल्कि नज़रिए पर निर्भर करता है।

नवारो की आक्रामक शैली, टकरावपूर्ण भाषा, व्यापार का ज़ीरो-सम दृष्टिकोण, और तथ्यों का ''सिलैक्टिव'' उपयोग, इस बात को दर्शाता है कि वे भारत के रूसी तेल आयात को नीति-आधारित आवश्यकता नहीं बल्कि ''मुनाफाखोरी योजना'' क्यों बताते हैं। यह संतुलित ऊर्जा विश्लेषण से कम, और उनके विशिष्ट दृष्टिकोण का विस्तार ज्यादा प्रतीत होता है: उत्तेजना के माध्यम से दबाव बनाना।

नवारो को व्यापक रुप से ''चीन विरोधी सख़्त नीति अपनाने वाला और सामान्य तौर पर व्यापार में ''सख़्त रुख रखने वाला'' कहा जाता है ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आक्रामक टैरिफ, सप्लाई चेन को अमेरिका में वापस लाने, और अमेरिकी आयात पर निर्भरता को कम करने का समर्थन किया। उनके रुख कई अन्य अर्थशास्त्रियों और यहां तक कि ट्रंप प्रशासन के कुछ सहयोगियों से भी अधिक कठोर माने जाते हैं।

जैसलमेर, बीकानेर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी तरह, बीकानेर जिले की पूगल तहसील के दीनसर व बराला गांव में 393.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बीकानेर तहसील के गांव सवाईसर, बज्जू तहसील के गांव बिकोलाई तथा पूगल तहसील के गांव करणीसर भाटियान में कुल 2320.46 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ ही लेख में भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की गई थी और वही टिप्पणियाँ कई अन्य मीडिया संस्थानों ने भी छापी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया और वरदराजन व फाउंडेशन को अंतरिम राहत दी। लेकिन उसी दिन गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करन थापर को दूसरी एफ.आई.आर. में समन भेज दिया। असम पुलिस की इन कार्रवाइयों की प्रेस संगठनों, सांसदों और आम जनता ने तीखी आलोचना की है। कहा जा रहा है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और ''द वायर'' के पत्रकारों को परेशान करने की कोशिश है।

निकाय चुनावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य स्तर पर समकालिक कठोर जातीय अध्ययन के आधार पर उनकी प्रकृति, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की स्थिति का गहन विश्लेषण हो। आयोग ने यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है और राज्य में ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिणक एवं राजनीतिक स्थिति का व्यापक डेटा संग्रह किया जा रहा है। इसके लिए आयोग ने समर्पित टीम गठित की है, जो विभिन्न स्तरों पर आंकड़े जुटाने का काम कर रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग को यह कार्य पूरा करने के लिए लगभग तीन माह का समय लग सकता है। इसके बाद ही पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

ऑन लाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

प्र.मंत्री मोदी ने कहा, इससे ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग के हानिकारक प्रभावों पर अंकुश लगेगा

- **मोदी ने कहा इस कानून से गेम की लत से मुक्ति दिलाई जा सकेगी।**

नयी दिल्ली, 22 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, गेम्स के जरिए पैसे लूटने पर रोक लगाना और ई-स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता देना है। इसके साथ ही इस कानून से नशे की लत से मुक्ति दिलाई जा सकेगी और आर्थिक नुकसान जैसे खतरों को भी रोका जा सकेगा।

संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। इस कानून को शैक्षिक खेलों और सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए लाया गया था। इस कानून में इस क्षेत्र के समन्वित नीति, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के लागू होने पर देश में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा तथा आनलाइन-गेमिंग के हानिकारक प्रभावों से बचाव होगा।

इस विधेयक के गुरुवार को राज्यसभा में पारित किए जाने के साथ इसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिल चुकी है।

मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।

प्र.मंत्री मोदी ने कोलकाता में 3 नए मैट्रो रुट का उद्घाटन किया

कोलकाता, 22 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपारा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा, सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और फिर मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो परियोजनाओं में शामिल श्रमिकों और स्कूली छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और शांतनु ठाकुर ने उनका अभिनंदन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ''आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपारा से बिमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है।''

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908